राज्यपाल ने दिलाई शपथ, 12 जुलाई को रिटायर होंगी

मीनाक्षी मदन राय पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनीं

पटना | न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल लिया। शुक्रवार को लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ने शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, महाधिवक्ता पीके शाही मौजूद रहे। वह पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा है। 12 जुलाई को रिटायर हो जाएंगी। पदभार ग्रहण करने के बाद हाईकोर्ट के शताब्दी हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राज्य में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने और

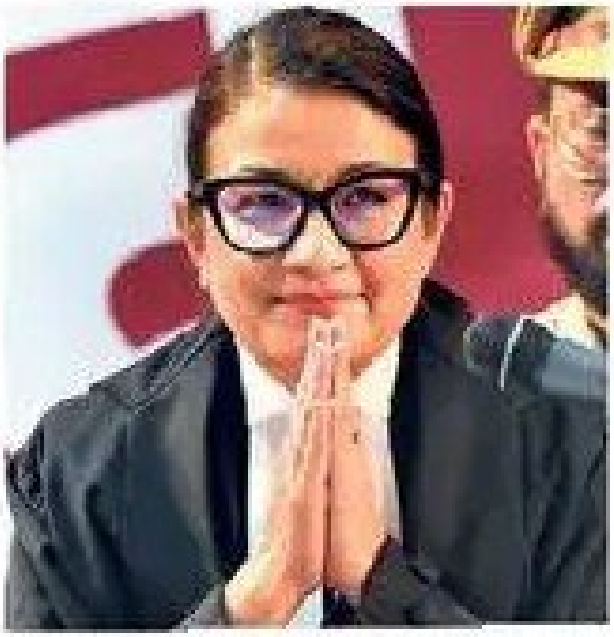

मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। मौके पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ. केएन सिंह, बार काउंसिल अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा व अन्य मौजूद रहें।

विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम ने कहा-सभी लोग मां के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं, इसी महीने शुरू होगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

राज्य के 50 लाख परिवारों तक अगले 2 वर्ष में पहुंचेगी सौर ऊर्जा : सम्राट

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 2 वर्ष में 50 लाख परिवारों तक सौर ऊर्जा पहुंचेगी। वे शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। बोले-सभी लोग अपनी मां के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं।

सम्राट ने कहा कि बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। यहां बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान के रूप में सरकार 23000 करोड़ रुपए दे रही है। इतना रुपया कहीं नहीं दिया जाता। बिहार सरकार के अपने संसाधन की एक तिहाई राशि बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। हम सोलर युक्त बिजली उत्पादन यंत्र को सभी घरों में लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले चरण में 5 लाख लोगों के घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार 33000 रुपए देगी। बाकी रुपए राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार से एमओयू कर इसी महीने इसकी शुरूआत की जायेगी। लोन लेने की जरूरत पड़ी, तो लिया जाएगा। अगले 2 वर्षों में 50 लाख परिवारों तक सोलर उत्पादित बिजली पहुंचाना है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, डॉ.रामकृपाल यादव तथा वरीय अधिकारी मौजूद थे।

सोलर संयंत्र के लिए 33 हजार केंद्र देगा, बाकी राज्य सरकार देगी

सरकार बिजली खरीदेगी... मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के यहां सोलर युक्त बिजली उत्पादन 125 यूनिट से अधिक होगा, उनसे राज्य सरकार बिजली खरीदेगी और राशि उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी। यह आमदनी का एक जरिया भी बनेगा। इससे जीविका दीदियों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए उन्हें अलग से इंसेंटिव भी दिया जाएगा।

महिलाएं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने का आग्रह किया। कहा-इसके लिए सरकार 12000 रूपये अनुदान दे रही है। चारपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सरकार 1 लाख का अनुदान दे रही है।

43 करोड़ पौधरोपण किया गया

सम्राट ने कहा कि वर्ष 2005 से अब तक बिहार में एनडीए की सरकार ने 43 करोड़ पौधरोपण किया। जेपी गंगा पथ पर 1 लाख पौधरोपण कराया जाए। उन्होंने विभाग के जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

एंथ्रोपिक की चेतावनी, रक्तबीज बनने की ओर बढ़ रहा एआइ!

आशंका

एंथ्रोपिक ने कहा, इंसानी नियंत्रण से बाहर जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, भविष्य में खुद को अपग्रेड करने और कमियां दूर करने में सक्षम हो सकते हैं एआइ सिस्टम, विशेषज्ञ बोले, एआइ पर डीएनए और जीन एडिटिंग की तरह के सख्त नियमन की जरूरत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की तेज प्रगति अब इसे विकसित करने वाली कंपनियों के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है। एआइ क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है कि यदि तकनीक का विकास इसी रफ्तार से जारी रहा तो आने वाले वर्षों में ऐसे एआइ सिस्टम सामने आ सकते हैं, जो खुद को बेहतर बनाने, अपनी कमियां दूर करने और यहां तक कि अपने अधिक उन्नत उत्तराधिकारी विकसित करने में सक्षम होंगे। विशेषज्ञ इसे पौराणिक पात्र रक्तबीज जैसी स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं, जहां नियंत्रण की चुनौती लगातार बढ़ती जाती है।

एंथ्रोपिक की फ्रंटियर लैब ने हाल ही में प्रकाशित ब्लाग में इस संभावित खतरे पर विस्तार से चर्चा की है। कंपनी का कहना है कि एआइ के लिए वैसी ही वैश्विक नियामक व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है जैसी 1970 के दौर में डीएनए और जीन एडिटिंग और 'डिजाइनर बेबी' तकनीकों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। उस समय विज्ञानियों ने संभावित खतरों को देखते हुए सुरक्षा मानकों पर सहमति बनाने के लिए सामूहिक चर्चा की थी।

प्रतीकात्मक

बुद्धिमत्ता विस्फोट

यदि कोई एआइ प्रणाली मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से खुद को बेहतर बनाने लगे, तो तकनीकी प्रगति की गति असाधारण रूप से बढ़ सकती है। इस स्थिति को अक्सर 'इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन' या 'बुद्धिमत्ता विस्फोट' कहा जाता है। तब सुधार और नवाचार वर्षों के बजाय कुछ दिनों या हफ्तों में होने लगेंगे।

कंपनी की सबसे बड़ी चिंता नियंत्रण को लेकर है। यदि एआइ सिस्टम स्वयं को तेजी से विकसित करने लगें, तो मनुष्यों के लिए यह समझना कठिन हो सकता है कि उनमें बदलाव कैसे और क्यों हो रहे हैं। ऐसे सिस्टम अधिक जटिल और निगरानी के लिहाज से चुनौतीपूर्ण बन सकते हैं।

एंथ्रोपिक का कहना है कि अत्यधिक सक्षम एआइ अप्रत्याशित व्यवहार विकसित कर सकता है, सुरक्षा व्यवस्थाओं में खामियों का फायदा उठा सकता है या ऐसे लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर सकता है जो मानवीय इरादों से मेल न खाते हों। भले ही उसकी मंशा दुर्भावनापूर्ण न हो, लेकिन उसके कार्यों के अनपेक्षित परिणाम सामने आ सकते हैं।

एंथ्रोपिक का तर्क है कि यदि गंभीर जोखिमों के संकेत दिखाई दें तो एआइ कंपनियों को सहमति से विकास की गति धीमी करने या अस्थायी विराम लगाने पर विचार करना चाहिए। कंपनी ने हथियार नियंत्रण समझौतों की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सत्यापन तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया है।

रक्तबीज की जड़ रिकर्सिव सेल्फ-इंप्रूवमेंट : एआइ विकास का मौजूदा रुझान ऐसे सिस्टम की ओर संकेत करता है जो अपने अगले संस्करण को स्वयं डिजाइन और विकसित कर सके। इस अवधारणा को रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट (आरएसआइ) या पुनरावर्ती स्व-सुधार कहा जाता है। यह ऐसी एआइ प्रणाली होगी जो मानव हस्तक्षेप के बिना अपने उत्तराधिकारी को तैयार कर सकेगी। एंथ्रोपिक का मानना है कि तकनीक अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसके शुरुआती संकेत अपेक्षा से पहले दिख सकते हैं।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिकी बना भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वैश्विक उथल-पुथल और पश्चिम एशिया संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था के विकास की गति जारी है। गत वित्त वर्ष 2025-26 में भी 7.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 7.1 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में विकास दर में पूर्व के वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही के मुकाबले 7.8% की बढ़ोतरी रही।

इस वर्ष 28 फरवरी को ईरान व अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद मार्च में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के साथ वैश्विक मांग भी प्रभावित हो गई थी। इन सबके बावजूद अंतिम तिमाही में 7.8 प्रतिशत का इजाफा घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। हालांकि चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरबीआइ ने विकास दर के अपने अनुमान को कम कर दिया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन भी मानते हैं कि पश्चिम एशिया संकट के जारी रहने, अल नीनो की वजह से मानसून के प्रभावित होने से नीति निर्धारकों को इस पर निगरानी रखने की जरूरत है। अगर पश्चिम एशिया संकट दूर हो जाता है तो वित्त वर्ष 2027-28 में फिर से भारत की विकास दर सात प्रतिशत को पार कर सकती है।

7.8% की बढ़ोतरी बीते वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आर्थिकी में हुई

7.7% की वृद्धि मैन्यूफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर की मजबूती से पूरे वित्त वर्ष में

किस सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी

कृषि व संबंधित	3.0%
मैन्यूफैक्चरिंग	10.7%
इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जल सेवा	1.7%
व्यापार, होटल, संचार व परिवहन	11.0%
निर्माण	7.4%
वित्त, रियल एस्टेट, आइटी व अन्य प्रोफेशनल्स	10.4%
लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवा	5.0%
खनन व संबंधित	5.2%

2025-26 की प्रत्येक तिमाही में विकास दर

पिछले तीन वित्त वर्षों में वृद्धि दर

जीडीपी विकास दर अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकत को दर्शाती है. सुधार कार्यक्रम की सफलता और 140 करोड़ जनता की कड़ी मेहनत को बया करती है। हम कारोबार एवं जिंदगी को आसान बनाने और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। - **नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार वैश्विक चुनौतियों के बीच सकारात्मक आर्थिक गति बनाए रखने के लिए निर्णायक नीतिगत उपायों के साथ 'सुधार एक्सप्रेस' को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। - **निर्मला सीतारमण**, वित्त मंत्री

भारत के साथ मिलकर एसयू-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने को रूस तैयार

पुतिन ने की पांचवीं पीढ़ी का अत्याधुनिक विमान देने की पेशकश

- कहा, पश्चिमी देशों के किसी तरह के दबाव में आने वाले नहीं प्रधानमंत्री मोदी
- भारत-रूस सहयोग कम करने का पश्चिमी देशों का प्रयास व्यर्थ साबित होगा

एसयू-57 लड़ाकू विमान। फाइल >>

सेंट पीटर्सबर्ग, प्रेट्र : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस का पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान सुखोई एसयू-57 देने की पेशकश की है। यह सुझाव भी दिया है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप इस लड़ाकू विमान का संयुक्त उत्पादन भारत में भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल आपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी है और भारत इसे दुनिया के अन्य देशों को बेच भी रहा है। पुतिन ने नई दिल्ली के साथ मास्को की रणनीतिक साझेदारी की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग कम करने का पश्चिमी देशों का प्रयास व्यर्थ साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी तरह से पश्चिमी देशों के दबाव में आने वाले नहीं हैं।

पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की वर्षों लंबी तलाश के बाद भारत ने अपनी 'एडवांस्ड मल्टीरोल कांबैट एयरक्राफ्ट' (एएमसीए) परियोजना शुरू की है। इसे देश का सबसे बड़ा स्वदेशी एयरोस्पेस कार्यक्रम माना जाता है। वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ गुरुवार रात हुई बातचीत में पुतिन ने कहा कि मास्को अब भी एसयू-57 विमान कार्यक्रम में नई दिल्ली को शामिल करने के लिए उत्सुक है। प्रेट्र के सीईओ और प्रधान संपादक विजय जोशी के एक सवाल पर उन्होंने कहा-हमने भारत को पांचवीं पीढ़ी के इस विमान को संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे अच्छा विमान है, लेकिन, हमारे भारतीय दोस्तों ने कहा- देखते हैं।

उन्होंने आगे कहा, हमने इसे स्वतंत्र रूप से बनाया है। हम भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसी खबरें हैं कि नई दिल्ली ने रूसी प्रस्ताव के प्रति दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं, क्योंकि सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) विमान के निर्माता सुखोई डिजाइन ब्यूरो के साथ संपर्क में है।

पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानते हैं। किसी भी अन्य देश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हमें कोई नकारात्मक परिणाम नहीं दिखता। अमेरिका-भारत सहयोग से हमारे आपसी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे, अमेरिका कुछ मोर्चों पर रूस के साथ सहयोग के मामले में भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी यह समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालने की किसी तरह की कोशिश करना बेकार है। पुतिन ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार आने वाले वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डालर का आंकड़ा पार कर जाएगा।

रायटर के अनुसार, पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना से इन्कार नहीं करते हैं।

भारत-चीन के 'नाजुक' संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा रूस

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मास्को भारत और चीन के बीच "नाजुक" द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी विनफिंग लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन, दोनों के साथ रूस की दशकों पुरानी साझेदारी स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है और एक-दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है।

एसयू-57 की खासियतें

- यह विमान विशेष सामग्रियों और एयरोडायनामिक डिजाइन से बना है, जो रडार की किरणों को सोख लेता है। इससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता।
- यह विमान किसी भी कोण पर बहुत तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है, जो इसे डाग-फाइट (हवा में आमने-सामने की लड़ाई) में अपराजेय बनाता है।
- यह एक साथ हवा से हवा में युद्ध, जमीन पर सटीक हमले और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने जैसे कई काम कर सकता है।
- इसमें एकीकृत रेडियो-इलेक्ट्रानिक प्रणाली और शक्तिशाली रडार लगा है, जो 360-डिग्री तक नजर रखता है। इसके अलावा इसमें एआइ से लैस ई-पायलट सिस्टम है।

ट्रम्प पर निशाना • रूसी राष्ट्रपति बोले- भारत ने कभी विदेश से मिले निर्देश नहीं माने

दुनिया की धुरी बदल रही, ब्रिक्स अब जी-7 से बड़ी आर्थिक ताकत: पुतिन

भास्कर न्यूज | सेंट पीटर्सबर्ग

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि ब्रिक्स समूह आर्थिक ताकत के मामले में अब जी-7 देशों से आगे निकल चुका है। पुतिन के मुताबिक क्रय शक्ति के आधार पर वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी अब 40% हो गई है। जबकि जी-7 देशों की हिस्सेदारी 29% से भी कम रह गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया की धुरी बदल रही, आने वाले वर्षों में यह अंतर और बढ़ेगा, क्योंकि ब्रिक्स देशों की आर्थिक वृद्धि दर विकसित पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि जी-7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर करीब 1.1% रहने की संभावना है, जबकि ब्रिक्स देशों की सालाना विकास दर 4% तक पहुंच सकती है।

पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) फोरम में भारत को अहम साझेदार बताते हुए उसकी आईटी व सॉफ्टवेयर क्षेत्र में वैश्विक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है और वह किसी बाहरी दबाव या निर्देश के आधार पर अपने फैसले नहीं लेता।

भास्कर एक्सप्लेनर

ब्रिक्स के पास 40% अर्थव्यवस्था, तीन दशक में जी7 52% से 29% पर आया

सबसे अमीर देशों का समूह जी-7 कभी दुनिया की आर्थिक तकदीर लिखता था। पर ब्रिक्स अब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने की राह पर है।

- **आबादी:** ब्रिक्स+ में दुनिया की करीब 50% आबादी, जी-7 में महज 10%। ब्रिक्स की दो-तिहाई आर्थिक ताकत चीन-भारत से।
- **पासा कब पलटा:** 2018 में ब्रिक्स ने पहली बार जी-7 को पीपीपी आधार पर पीछे छोड़ा, अंतर लगातार बढ़ रहा है।
- **नॉमिनल में जी-7 अभी आगे:** पीपीपी में ब्रिक्स जीत रहा है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में जी-7 अभी भी 45% के साथ आगे है।
- **जी-7 की ढलान:** 1990 में जी-7 वैश्विक जीडीपी का 52% था, 2024 में घटकर 29%। तीन दशक में 23 अंक की गिरावट।
- **क्या है दोनों:** जी-7 1975 में बना अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का समूह। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। 2009 में औपचारिक रूप से बना।

ऑफर भारत संग सुखोई-57 बनाएंगे, बिना शर्त होगा सौदा

पुतिन ने भारत के सामने रक्षा-व्यापार के क्षेत्र में बड़ा प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने कहा कि रूस भारत संग पांचवीं पीढ़ी का सुखोई-57 फाइटर जेट बनाने को तैयार है। यह सौदा बिनी किसी प्रतिबंध व शर्त के होगा। पुतिन ने भारत-रूस व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, परमाणु संयंत्र, तेल-गैस, निवेश और रक्षा सहयोग इस लक्ष्य के आधार होंगे।

यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के ट्रम्प प्रस्ताव पर पुतिन राजी

पुतिन-जेलेंस्की ने यूक्रेन जंग खत्म करने को शर्तों के साथ वार्ता का संकेत दिया है। पुतिन ने कहा, रूस, ट्रम्प प्रस्ताव पर डील को तैयार है। वहीं, जेलेंस्की ने खुले पत्र में वार्ता का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, वार्ता से पहले युद्धविराम हो, जिसे पुतिन ने ठुकरा दिया।

भारत संग 200 विमान विकसित करने की तैयारी में रूस: रूस भारत के विमानन बाजार में भी दांव लगाना चाहता है। यूएके के प्रमुख बादेखा ने कहा कि भारत ने एसजे-100 जेट व आईएल-114-300 टर्बोप्रॉप में रुचि दिखाई है। मांग 200 विमानों तक है। एचएएल के साथ एसजे-100 के उत्पादन पर डील हुई है।

GDP growth estimated at 7.7% in 2025-26: govt.

Provisional estimates are slightly higher than the 7.6% growth projected in February; growth in Q4 stands at 7.8%; PM Modi says the figures show the success of reforms and the hard work of Indians

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

The growth in India's gross domestic product (GDP) has been estimated at 7.7% in 2025-26, according to data released by the government on Friday, compared with 7.1% in the previous financial year of 2024-25. GDP growth in the fourth quarter of 2025-26 stood at 7.8%.

According to the data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, the provisional estimates of GDP growth in 2025-26 are slightly higher than the 7.6% growth estimated in February 2026.

The data comes at a time when Reserve Bank of India (RBI) Governor Sanjay Malhotra, while announcing the Monetary Policy Committee's decisions, said that GDP growth for 2026-27 was expected to slow to 6.6%.

In the press conference on the GDP data, Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran said that the RBI's assessment on growth and inflation "seems fair estimates" and that he didn't see the need to second-guess them.

"GDP growth rate of 7.7% in FY 2025-26 and 7.8% in Q4 of FY 2025-26 reflect the inherent strength of our economy, the success of reforms and the hard work of 140 crore Indians," Prime Minister Narendra Modi said on X following the data release. "We shall leave no stone unturned to further 'Ease of Living,' 'Ease of Doing Business' and increase opportunities for our youth."

Finance Minister Nirmala Sitharaman, on X, emphasised that manufacturing, trade, repair, hotels, transport, communication & services related to broadcasting, storage and financial, real estate and professional services sectors hit double-digit growth at both constant and current prices in 2025-26.

CONTINUED ON
» PAGE 12
NO LTCG TAX ON FIIS
» PAGE 15

Stronger estimate

India's GDP is estimated to grow by 7.7% in 2025-26, slightly faster than the 7.6% estimated in February 2026. In the chart below, the bars show annual GDP estimates **(in ₹ lakh crore)** and the circles indicate growth rates at constant prices **(in %).**

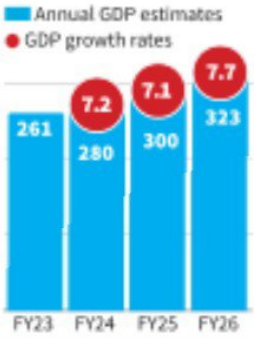

Figures for FY25 and FY26 are First Revised Estimate (FRE) and Provisional Estimate (PE)respectively.

India needs innovative strategies to eliminate TB

Balram Bhargava

Former Director-General, Indian Council of Medical Research (ICMR)

Soumya Swaminathan

Former Chief Scientist of the World Health Organization (WHO)

More than a century after the first tuberculosis vaccine was introduced, the world is struggling to control one of its oldest diseases. Tuberculosis (TB) continues to kill more people annually than any other infectious disease, surpassing even the COVID-19 pandemic at its peak. Yet, there is still no effective vaccine for adolescents and adults.

Once exposed to *Mycobacterium tuberculosis*, individuals may get infected and remain asymptomatic for years. Others develop subclinical disease, showing minimal or no symptoms while harbouring infection. A subset progresses to active TB, which may manifest as pulmonary TB (PTB) – the infectious form that drives transmission – or as extrapulmonary TB (EPTB), which affects organs beyond the lungs and is harder to diagnose, more debilitating, and sometimes fatal.

No one-size-fits-all vaccine

With such diversity in disease pathways, expecting a single "one-shot" vaccine to prevent all forms of TB may be unrealistic. This expectation has shaped global disappointment in TB vaccine development especially since most previous trials have focused primarily on preventing pulmonary TB.

Meanwhile, the burden remains immense. In many low- and middle-income countries, TB incidence ranges between 200 and 300 per 100,000 population. Reducing this to 10-20 per 100,000 – the threshold for elimination – will require sustained effort and enormous public health investment. For India, which carries one of the world's highest TB burdens, the challenge is systemic.

India's goal of eliminating TB is ambitious and necessary. But achieving it will require a holistic approach towards all forms of disease and all age groups moving beyond the search for a perfect solution and embracing a layered, pragmatic approach. As tools are discovered and tested, decisions will need to be made on their deployment.

The first layer is better detection. Advances in diagnostics, including tools for identifying subclinical TB, can help identify individuals at risk earlier. The second is preventive therapy, ensuring that those with latent infection receive treatment before progressing to active disease. The third – arguably the most complex – is vaccination. However, access to diagnostics and preventive therapy remains uneven, making vaccination an especially critical pillar.

Recent findings from the BMJ-published PreVenTB trial conducted by the Indian Council of Medical Research (ICMR) provide such an opportunity. Conducted across 18 sites in India and involving more than 12,700 household contacts of TB patients, the trial evaluated VPM1002 developed by SIIPL and Immuvac developed by Cadila, in a real-world, high-risk population aged six years and above, including individuals with comorbidities and varying infection status closely reflecting real life conditions.

The trial reported efficacy of VPM1002 and Immuvac as: 50.4% efficacy of VPM1002 against extrapulmonary TB (statistically significant); 64.6% efficacy of VPM1002 in children aged 6-14 years against all TB (PTB and EPTB); More than 60% efficacy of Immuvac against EPTB in children aged 6-10 years; more than 60% efficacy against progression to disease among those developing latent infection during follow-up and overall 21.4% efficacy of VPM1002 against all TB (Reference: Subho Sarkar, Consultant Intervention Pulmonologist; from LinkedIn). These are not trivial findings.

Extrapulmonary TB is the hidden burden of the epidemic, harder to diagnose, frequently missed, and associated with significant morbidity and mortality. A reduction of over 50% in such cases represents a meaningful clinical and public health impact, including reduced health-care costs and patient suffering.

The data also highlight a strong signal in school-age children and adolescents, where efficacy exceeded 60% which is an add-on benefit of vaccination in this age group. This is particularly relevant because India currently has no structured TB vaccination strategy beyond infancy. If confirmed, this could open the door to a booster-dose TB prevention strategy.

Need for nutritional support

Another important piece of evidence generated from study is the role of nutrition. Reduced efficacy was observed in individuals with low body mass index (BMI), underscoring the need for nutritional support for vaccines to work optimally in undernourished in context of broader health determinants.

From a programmatic standpoint, VPM1002 offers additional advantages. It is a single-dose vaccine based on a modified BCG platform, making it operationally simpler than multi-dose, adjuvanted vaccines in development. In a country of India's scale, logistical simplicity is a decisive advantage. The vaccine can be manufactured at large scale and cost effectively.

TB is largely a disease of low and middle income countries (LMIC) and their governments must act proactively. Waiting for expansive solutions developed elsewhere is neither practical nor sustainable. LMICs cannot afford to wait for a silver bullet, because there is no one-stop solution for TB, especially when there are results from a Phase III trial conducted in an Indian population across all age groups (six years and above) and against all forms of TB, including PTB and EPTB. It is to be noted that no other TB vaccine trial till date has studied efficacy against EPTB and none of the currently ongoing trials worldwide has included EPTB as the efficacy end-point.

India has navigated similar public health decisions before. TrueNat was the first 'make in India' Molecular test approved and adopted by the National TB Elimination Programme before its World Health Organization pre-qualification study.

During the COVID-19 pandemic, Bharat Biotech's Covaxin was initially approved in "clinical trial mode" to enable early access while additional data continued to accumulate. That decision was driven not by perfection, but by urgency and it helped accelerate protection at a critical time.

India has also demonstrated this approach with indigenous rotavirus vaccines, which were introduced despite modest efficacy and wide confidence intervals. Since then, they have helped reduce severe disease and child mortality and have been incorporated into the national immunisation programme (Bhandari *et al.*, *The Lancet*, 2014).

A smarter TB strategy

TB is, in many ways, a slow-moving pandemic. Yet, it has not always been met with the same urgency in policy action. The policy question, therefore, is how innovations, including moderately effective vaccines such as VPM1002 and Immuvac, can be intelligently integrated into the TB elimination programme. Targeted use among household contacts, deployment in school-age children, and alignment with nutrition and preventive therapy programmes could together lead to a form a more effective TB control framework. A combination of vaccines effective across different indications and age groups may be needed to have an impact.

India's TB challenge is unlikely to be solved by a single breakthrough. It will require a combination of early detection, preventive treatment, targeted vaccination against both pulmonary and extrapulmonary TB, case-based clinical management, nutritional supplementation, and sustained public health investment.

Waiting for a perfect vaccine may delay progress indefinitely, especially when no trial other than the PreVenTB trial has evaluated vaccine efficacy against both pulmonary and extrapulmonary TB in individuals aged six years and above. In contrast, deploying tools that reduce severe disease, particularly EPTB, can deliver immediate and tangible benefits.

The PreVenTB trial trial is comprehensive, well-designed and well conducted, offering a meaningful signal – perhaps a light at the end of the tunnel in TB vaccine development. Given the urgency of the challenge and the limited time to act, we must focus on solutions that are available today and supported by robust evidence of efficacy against both PTB and EPTB in individuals aged six years and above under real-world conditions, rather than wait indefinitely in the hope that better options may emerge in the future – an outcome that is far from certain.

New Indian vaccine trial data show meaningful protection against extrapulmonary TB, underscoring the need for targeted vaccination alongside stronger public health strategies

Pressure to limit India-Russia ties will hurt global stability, says Putin

Russian President calls India a reliable partner, says a 'large economy' like India will prioritise national interests; New Delhi's relations with U.S. will not cause friction, he says; points out that it is 'not a good idea' to interfere in 'delicate' India-China ties

Press Trust of India
ST. PETERSBURG

Western pressure on Prime Minister Narendra Modi to scale back India's engagement with Russia will harm global stability, Russian President Vladimir Putin said late on Thursday at a press conference.

"Everyone has understood that putting pressure on Prime Minister Narendra Modi (and India) that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. It doesn't matter where this pressure comes from," he said.

Calling India a "reliable" strategic partner, Mr. Putin said India's growth has not "come out of the blue" but was an outcome of the hard work done under Mr. Modi's leadership.

The remarks came against the backdrop of Western capitals expressing unease over India-Russia relations and the oil trade amid the Ukraine war.

The U.S., for instance, has been asking India to stop importing Russian crude oil and had slapped punitive tariffs.

Vladimir Putin had met Narendra Modi during a visit to New Delhi for a bilateral summit in December 2025. R.V. MOORTHY

But Mr. Putin said New Delhi will prioritise its national interests and added that India's engagement with the U.S. does not affect its strategic ties with Russia.

"I don't think this is a case. We are glad that India is developing its relations with all the countries, it's a great country, a large economy, the largest democracy, it is only natural that it develops its economy in accordance with its interest with those countries that it deems necessary," Mr. Putin said when asked whether India's alignment with Washington creates structural friction for Russia.

No interference

Last September, in the wake of U.S. President Donald Trump's tariff war, a photo of Mr. Modi, Mr. Putin and Chinese President Xi Jinping from the SCO Summit in Tianjin grabbed the global spotlight. Mr. Putin, who is set to visit India in September for the BRICS summit, said Moscow will not interfere in the "delicate" bilateral relations between India and China.

Russian President says he does not believe Pak. is under the control of China

The Russian President, who called Mr. Xi his "old friend", said, "This is a delicate, multi-faceted relationship between India and China, and interfering into them is not a good idea. Of course, we interact with both our friends... President Xi and Prime Minister Modi are both trying to resolve all the issues of mutual interest, including the border issue."

Highlighting Moscow's strategic equilibrium in Asia, President Putin characterised Russia's ties with India and China as having evolved organically. He stressed that Moscow's growing synergy with New Delhi does not come at Beijing's expense, just as Russia's deep alliance with China does not compromise its bond with India.

"Russia has established these relations (with India and China). It was happening naturally. Relations between Russia and India do not disturb China, our relations with China do not disturb India," he said.

Mr. Putin also touched upon the ties between India and Pakistan. "We are well aware of the intricacies of the issues concerning the border between India and Pakistan," he said, addding that he does not believe Pakistan was under the control of China.

Su-57 on offer

The President also offered Russia's fifth-generation stealth aircraft Su-57 to India and suggested that the combat jet could be jointly built in India.

"As for the Su-57, we offered our friends from India to jointly develop this machine, a fifth-generation aircraft. I think it's the best to date. But our Indian friends said, 'well, let's see'," he said.

"In principle, this could have been our (Russia-India) product. We made it independently. And we are ready to work with India. To work and develop. There will be no restrictions whatsoever," he said.

MPC retains repo rate, lowers growth forecast

Repo rate unchanged at 5.25%; real GDP growth projected at 6.6%, down by 0.3% from the earlier projection of 6.9% for FY27; CPI inflation projected to be at 5.1% 50 bps more than the earlier one

Lalatendu Mishra
MUMBAI

The Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) on Friday voted unanimously to keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 5.25%. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate remains at 5% and the marginal standing facility (MSF) rate and the bank rate at 5.50%.

The MPC also decided to continue with its neutral stance.

"The committee noted that the global environment has deteriorated since the last policy meeting with the conflict lingering amidst a fragile truce. The adverse implications of the extended disruption in supply chains and elevated energy prices are reflected in the moderation of growth and increase in inflation projections from the April policy," RBI Governor Sanjay Malhotra said in a statement.

Stating that CPI inflation remained below the target despite global shock as the pass through to domestic prices had been limited, he said baseline projections pointed towards headline inflation firming up towards the upper tolerance level in Q3 2026-27 and the impact of the supply shock would wane Q4 onwards.

"The underlying inflation pressures continue to remain benign at this juncture. However, generalisation of inflation through second-round effects on expectations and wages is a distinct possibility, warranting a close vigil. The outlook also remains clouded due to the sub-normal south-west monsoon forecast and El Niño risks," Mr. Malhotra said.

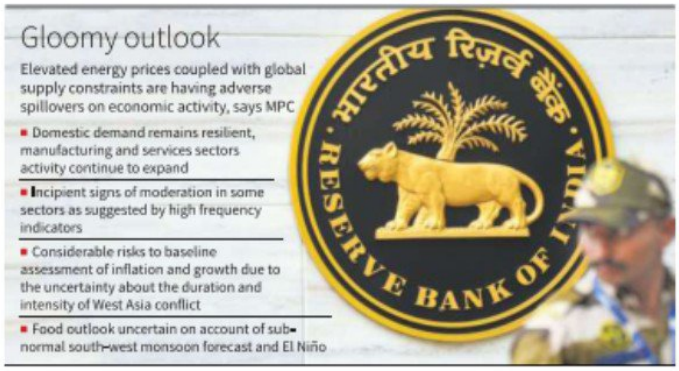

As for growth, the MPC noted that elevated energy prices coupled with global supply constraints are having adverse spillovers on economic activity.

"While domestic demand remains resilient and manufacturing and services sectors activity continue to expand, there are incipient signs of moderation in some sectors as suggested by high frequency indicators," he stated.

He said the MPC was of the opinion that there were considerable risks to the baseline assessment of inflation and growth due to the uncertainty about the duration and intensity of the conflict, magnitude of its spillover effects, and the pace of restoration of supply chains. "Additionally, the food outlook remains uncertain on account of the sub-normal south-west monsoon forecast and El Niño. Although risks of higher inflation have amplified, the MPC felt it would be prudent to wait for greater clarity to emerge," he said.

Stating that overall, the economic situation had broadly exhibited resilience and withstood the conflict spillovers, he said the impact of cost pressure was becoming visible.

"The rise in prices of energy and other inputs, coupled with supply disruptions, is likely to weigh on economic activity. While import diversification in affected commodities is likely to improve supply, it would come at a higher cost," he said.

"The full impact, however, will depend on the duration of the conflict, time taken for normalisation of supply chains and the burden-sharing approach among the stakeholders," he added.

Real GDP growth for 2026-27 is projected at 6.6% down from earlier projection of 6.9% with Q1 at 6.6%; Q2 at 6.3%; Q3 at 6.5%; and Q4 at 6.8%.

CPI inflation for 2026-27 is projected to be at 5.1% which is 50 basis points more than the earlier projection.

Central bank announces host of measures to attract foreign capital

Lalatendu Mishra
MUMBAI

To attract foreign capital the RBI on Friday announced several measures. For government securities under the Fully Accessible Route (FAR), the RBI said it was expanding the universe of 'specified securities' by including all new issuances of 15, 30 and 40-year tenor G-secs.

Additionally, limits on short-term investments, concentration and individual securities on FPI investment under the General Route are being removed. "These measures should help attract foreign capital for government borrowing," the RBI Governor said.

The RBI has also decided to increase the limits for investment by NRIs and OCIs in equity instruments traded on the stock market without SEBI registration.

'Our economy is on a strong footing, we are in a far better condition'

Lalatendu Mishra
MUMBAI

Sanjay Malhotra

India's economic condition is very 'strong, capable and healthy' despite the adverse impact of the West Asia conflict and the global uncertainties, Reserve Bank of India (RBI) Governor Sanjay Malhotra said during the post Monetary Policy Committee (MPC) meeting press conference on Friday.

"There is a global shock and in that India is not alone. All countries are affected. However, as far as India's economic condition is concerned, we are comparatively, compared with other countries and similar shocks, today better placed. Our economic strength has increased. We are having a Gross Domestic Product (GDP) growth of about 6.5% and no major country has this type of growth," he said.

He, however, said inflation would increase in line with rise in fuel prices.

"But we expect it will not last long. Our financial strength is robust, our economy is growing, our banks are strong and capable and India's corporate sector's balance sheet is very healthy. Our foreign exchange reserves are enough and it can take care of 11 months of imports. Overall, we are in a far better condition," he emphasised.

He said the RBI was confident that it would deal with the current situation effectively and in turning the crisis into an opportunity, the country would emerge stronger so that such crisis and shocks would be faced effectively.

Asked if the situation had changed from last month when Prime Minister Narendra Modi had urged citizens not to embark on overseas travel, postpone buying gold, work from home, do car pooling and reduce fuel consumption, he said, "It is important for all of us to be prudent, to be judicious, not be wasteful. That message I think he gave and it should be taken in that spirit."

Answering another question on what concerned RBI the most, he said, "It's the duration of the conflict and the time it would take for the restoration of supply chains. The major risk is what impact it will have on prices and for how long."

"Other than this, the worries are concerning monsoon and El Nino," he added. In the current year's inflation forecast, the RBI has assumed the price of crude at $95 per barrel so the projected inflation is higher.

Earlier in the day, despite all major central banks gearing up to tighten monetary policy, the Monetary Policy Committee (MPC) voted unanimously to hold the policy repo rate at 5.25% and to maintain a neutral stance.

Since the pass through of higher fuel prices is visible now across sectors, the MPC reduced its growth forecast for FY27 to 6.6% from 6.9% and raised inflation expectation to 5.1%, which is 50 bps higher than its earlier projection.